भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 69

दिनांक 29.11.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत-चीन संबंधों पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का प्रभाव

69. **श्री दयानिधि मारनः**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत-चीन डिसइंगेजमेंट समझौते को आगे बढ़ाने में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या शिखर सम्मेलन की समय-सीमा से किसी अनसुलझे मुद्दे को शीघ्र सुलझाने में मदद मिली और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सीमावर्ती मामलों की संवेदनशीलता को देखते हुए, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर होने वाली प्रगति और बदलावों के बारे में जनता को सूचना देने के लिए समय-समय पर अद्यतन जानकारी प्रदान करती है अथवा श्वेत पत्र जारी करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सीमा समझौते पर चीन की सरकार की ओर से कोई औपचारिक बयान आया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस तनावपूर्ण स्थिति में ढील दिए जाने की शर्तों का सार्वजनिक रूप से समर्थन करने में चीन की ओर से किसी अनिच्छा का पता चला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

(च) क्या वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ने से रोकने के लिए भविष्य में होने वाली गलतफहमियों या छोटी- मोटी घटनाओं से निपटने के लिए कोई सुस्थापित तंत्र मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या भारत और चीन के बीच वीजा जारी करने के नियमों को आसान बनाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश मंत्री

[डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर]

(क) से (छ) वक्तव्य सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"**भारत-चीन संबंधों पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का प्रभाव**" के संबंध में दिनांक 29.11.2024 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *69 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित वक्तव्य

(क) से (छ): प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 अक्टूबर 2024 को कज़ान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग से मुलाकात की।

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सेनाओं को पूरी तरह हटाए जाने तथा भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में 2020 में सामने आए प्रासंगिक मुद्दों के पूर्ण समाधान के लिए किए गए समझौते का स्वागत किया। उन्होंने मतभेदों और विवादों का उपयुक्त तरीके से समाधान करने और इनके कारण सीमा क्षेत्रों में शांति एवं सौहार्द भंग न होने देने के महत्व पर बल दिया।

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने 22 अक्टूबर 2024 को नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा , "हाल के समय में, चीन और भारत ने राजनयिक एवं सैन्य माध्यमों से गहन संप्रेषण के उपरांत सीमा क्षेत्र से संबंधित मुद्दों के समाधान पर पहुँचे हैं। चीन इस मामले में हुई प्रगति की सराहना करता है और इन संकल्पों के ठोस कार्यान्वयन के लिए भारत के साथ काम करना जारी रखेगा।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक के बाद चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया कि "दोनों नेताओं ने सीमा क्षेत्रों में प्रासंगिक मुद्दों के समाधान के संबंध में गहन संवाद के माध्यम से दोनों पक्षों द्वारा हाल ही में की गई महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की।"

सरकार ने मुद्दों के समाधान में प्रमुख उपलब्धियों के बारे में संसद को नियमित रूप से जानकारी दी है और प्रेस विज्ञप्तियों और ब्रीफिंग के माध्यम से भी सूचना जारी की है। रक्षा मंत्री ने 15 सितंबर 2020 और 11 फरवरी 2021 को चीनी पक्ष के साथ सेनाओं के हटाए जाने से संबंधित चर्चाओं में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में संसद को जानकारी दी थी। सरकार ने इस संबंध में 15 सितंबर 2020 और 12 फरवरी 2021 को प्रेस वक्तव्य भी जारी किए।

सरकार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी भी तरह के अतिक्रमण के मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ सीमा कार्मिक बैठकों, फ्लैग बैठकों, भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र की बैठकों, हालिया भारत-चीन कोर कमांडर स्तर के बैठक तंत्र की बैठक के साथ-साथ राजनयिक माध्यमों सहित स्थापित तंत्रों के माध्यम से नियमित रूप से उठाती है।

23 अक्टूबर 2024 को कज़ान में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक के दौरान इस बात पर सहमति बनी कि द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और उनका पुनर्निर्माण करने के लिए विदेश मंत्री और अन्य अधिकारियों के स्तर पर प्रासंगिक संवाद तंत्र का उपयोग किया जाएगा। विदेश मंत्री ने 18 नवंबर 2024 को जी20 शिखर सम्मेलन के

दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। यह चर्चा भारत-चीन संबंधों से जुड़े आगामी कदमों पर केंद्रित रही। इस बात पर सहमति बनी कि विशेष प्रतिनिधियों और विदेश सचिव-उप मंत्री तंत्र की बैठक जल्द ही होगी। जिन कदमों पर चर्चा हुई, उनमें कैलाश मानसरोवर यात्रा तीर्थयात्रा को फिर से शुरू करना, सीमा पार नदियों से संबंधित आंकड़े साझा करना, भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें तथा मीडिया आदान-प्रदान शामिल थे।

*****